बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 174 ● नई दिल्ली ● शनिवार 25 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को हाईकोर्ट से राहत, जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील खारिज

दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील खारिज कर दी। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से संबंधित है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दुड़ेजा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने पाया कि जमानत मिलने के बाद चार साल से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है। अदालत ने कहा कि वह पहले के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। इशरत जहां को मार्च 2022 में दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत मिली थी।

राहुल के ध्रुवीकरण वाले आरोप पर बीजेपी का पलटवार, किरेन रिजिजू बोले- कांग्रेस का स्टैंड ही साफ नहीं है

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 24 अप्रैल को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की, जब राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल का ध्रुवीकरण करने और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को राय में लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने का आरोप लगाया था। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान में विरोधाभासों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहां राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहीं वे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की इस बात के लिए आलोचना भी कर रहे हैं कि उसने भाजपा को अपनी पकड़ मजबूत करने दी। रिजिजू ने कहा कि यह हैरान करने वाला है। एक तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है, वहीं दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि टीएमसी की ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण भाजपा पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतेगी! पिछले दिन, राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए कहा था कि अगर ममता जी ने स्वच्छ सरकार चलाई होती और पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण न किया होता, तो भाजपा के लिए बंगाल में पैठ बनाना नामुमकिन होता। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ लड़ेगी और उसे हरा सकती है। इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की महत्वपूर्ण जीत की भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने एक आंतरिक आकलन का हवाला दिया था जिसमें संकेत दिया गया था कि पार्टी पहले चरण में लड़ी गई 152 सीटों में से 110 सीटें हासिल कर सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक की रिकॉर्ड मतदान दर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए जनता के समर्थन को दर्शाती है, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के प्रभाव के अंत का संकेत है। उन्होंने कहा कि भाजपा की बंगाल टीम ने अपना आकलन कर लिया है। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 152 सीटों में से भाजपा 110 से अधिक सीटें जीत सकती है। दूसरे चरण के मतदान को भी ध्यान में रखते हुए, भाजपा बंगाल में सरकार बनाने के लिए तैयार है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को शाम 6 बजे समाप्त हुआ, जिसमें 91.83 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। उच्च मतदान ने कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई एक सशक्त चुनाव प्रक्रिया को रेखांकित किया।

जनरल नरवणे के खुलासे से झूठ का पर्दाफाश? बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल

नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा, जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन के हाथों क्षेत्रीय नुकसान की बात को सिरे से खारिज कर दिया। फरवरी में संसद के बजट सत्र के दौरान, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जनरल नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से कुछ अंश उद्धृत करने का प्रयास किया। हालांकि, अध्यक्ष ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उस समय पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि नरवणे ने कहा है कि चीन को एक इंच भी जमीन नहीं दी गई। राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया, लेकिन अब नरवणे ने अपनी चुप्पी तोड़कर राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। जनरल नरवणे का हवाला देते हुए भाजपा नेता ने इस बात पर जोर दिया कि 2020 में चीन के साथ हुए गतिरोध के दौरान सेना को राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। जनरल नरवणे ने विवाद पर खुलकर बोलते हुए कहा कि अप्रकाशित दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मुझे और सशस्त्र बलों को राजनीति में घसीटना पूरी तरह से अनुचित है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की जमीनी हकीकत और बीजिंग के साथ जारी सीमा तनाव के बारे में पूछे जाने पर जनरल नरवणे ने कहा कि सभी शंकाओं को एक ही बार में दूर करने के लिए, बस चीनियों से पूछिए कि क्या उन्होंने हाल ही में भारत में कोई बढ़त हासिल की है। फरवरी में, जनरल नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी देश में राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गई, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में इस पुस्तक के कुछ अंश उद्धृत करने का प्रयास किया। अप्रकाशित आत्मकथा से उद्धरण देने की अनुमति न मिलने के बाद, गांधी को सत्र के शेष समय के दौरान इसकी एक प्रति लाते हुए देखा गया। पुस्तक के अंशों का हवाला देते हुए, कांग्रेस सांसद ने दावा किया था कि पूर्व सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह और अन्य लोगों को चीनी टैंकों के आने के बारे में सूचित किया था, और आरोप लगाया था कि सरकार की ओर से लंबे समय तक कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं मिली।

कोई अदालत नाबालिग को गर्भावस्था बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग, को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को सात महीने से अधिक की गर्भावस्था को मेडिकल तरीके से खत्म करने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि इस मामले में गर्भ अनचाहा है। साथ ही, उसने पहले दो बार आत्महत्या का प्रयास किया है, ऐसे में गर्भावस्था जारी रखना उसके हित में नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि गर्भवती महिला की पसंद सर्वोपरि है, न कि जन्म लेने वाले बच्चे की। अदालत ने कहा कि जबरन गर्भावस्था को जारी रखने से नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और समग्र विकास पर गहरा असर पड़ सकता है। पीठ ने कहा कि महिला की प्रजनन संबंधी स्वायत्तता को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। यदि किसी महिला को अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा, अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार, खासकर प्रजनन से संबंधित मामले, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अभिन्न हिस्सा है। इस अधिकार को गलत प्रतिबंध लगाकर कमजोर नहीं किया जा सकता, खासकर नाबालिगों और अनचाहे गर्भ के मामलों में। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोई भी अदालत किसी भी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था के लिए मजबूर नहीं कर सकती और खासकर नाबालिग को तो बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी महिला, खासकर नाबालिग, को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था के लिए बाध्य करना न सिर्फ उसकी आजादी की अनदेखी होगी, बल्कि इससे उसे गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात भी पहुंच सकता है। पीठ ने यह भी साफ किया कि यह तर्क देना आसान है कि यदि महिला बच्चे को पालना नहीं चाहती तो उसे गोद दे सकती है, लेकिन अनचाहे गर्भ के मामलों में यह तर्क ठीक नहीं है। अदालत ने कहा कि सांविधानिक अदालतों को ऐसे मामलों में गर्भवती महिला के हितों और परिस्थितियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि जन्म लेने वाले बच्चे को। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अनचाहे गर्भ को जारी रखने पर जोर दिया जाएगा, तो लोग अवैध गर्भपात केंद्रों का सहारा लेने को मजबूर होंगे, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा बढ़ेगा।

छात्रों की कथित हिरासत का मामला,हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, दिए सीबीआई जांच के संकेत

नई दिल्ली ।दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर छात्रों और एक्टिविस्ट्स की कथित अवैध हिरासत और यातना के मामले में सही कार्रवाई नहीं हुई तो जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की बेंच ने दिल्ली पुलिस की तरफ से सीलबंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट देखी लेकिन उससे संतुष्ट नहीं दिखी. कोर्ट ने कहा कि पुलिस का अब तक का रवैया भरोसेमंद नहीं है और आरोप बेहद गंभीर हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेंच ने सख्त लहजे में कहा हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे. अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम सीबीआई जांच के आदेश दे देंगे. ऐसा लग रहा है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम जांच आपसे लेकर सीबीआई को दे दें. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चाहे आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों पुलिस कानून की तय प्रक्रिया को नहीं तोड़ सकती. कोर्ट ने कहा क्या किसी पर आरोप लगते ही आप उसे उठा लेंगे. ऐसा नहीं चलेगा. कानून में जो प्रक्रिया तय है उसका पालन करना ही होगा.यह मामला मार्च 2026 में कुछ छात्रों और एक्टिविस्ट्स को कथित तौर पर हिरासत में लेने से जुड़ा है. इस पर कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिकाएं दाखिल की गई हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन छात्रों से एक महिला के गायब होने के मामले में पूछताछ की गई थी और उसी दिन उन्हें छोड़ दिया गया था. पुलिस ने यह भी दावा किया कि सभी आरोप जैसे अपहरण, जबरन हिरासत, मारपीट और उत्पीड़न झूठे और बेबुनियाद हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल उठाए. पहले कोर्ट ने जिन जगहों के सीसीटीवी सुरक्षित रखने को कहा था उनमें से दो जगहों के कैमरे काम नहीं कर रहे थे. इस पर भी बेंच ने नाराजगी जताई. छात्रों की ओर से पेश सीनियर वकील रेबेका जॉन ने कहा कि स्पेशल सेल के सीसीटीवी फुटेज बेहद अहम हैं क्योंकि इससे यह साफ हो सकता है कि छात्रों को कितनी देर तक वहां रखा गया. वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से वकील संजीव भंडारी ने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि किसी तरह की प्रताड़ना नहीं हुई. उन्होंने यह भी बताया कि एफआईआर साझा न करने के पीछे सक्षम प्राधिकारी के निर्देश हैं. आखिर में कोर्ट ने कहा कि वह पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और पूरे केस की फाइल कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को हाई कोर्ट करेगा.

जीएसटी विभाग में 162 अधिकारियों का फेरबदल, अनियमितताओं पर सीएम रेखा गुप्ता ने लिया एक्शन

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रेड एंड टैक्सेस (जीएसटी) विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सख्त नीति को सख्ती से लागू किया है। यह कदम विभाग के भीतर सामने आई गंभीर अनियमितताओं पर संज्ञान लेते हुए उठाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं। कुल 162 अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया है। इनमें तीन सहायक आयुक्त भी शामिल हैं। ये सभी अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात थे, जिससे कार्यप्रणाली में जड़ता आ गई थी। 8 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री के विभाग दौरे के दौरान ये अनियमितताएं सामने आई थीं। मुख्यमंत्री ने इन गंभीर अनियमितताओं पर तुरंत संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा, यह मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया।

अधिकारियों का विस्तृत विवरण

तबादला किए गए कुल 162 अधिकारियों में विभिन्न ग्रेड के कर्मचारी शामिल हैं। इनमें 58 अनुभाग अधिकारी ग्रेड-1 के अधिकारी हैं। 22 सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड-2 के कर्मचारी भी स्थानांतरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 74 वरिष्ठ सहायक ग्रेड-3 के अधिकारी शामिल हैं, जो विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे। 5 कनिष्ठ सहायक ग्रेड-4 के कर्मचारियों का भी तबादला हुआ है, जिससे निचले स्तर पर भी बदलाव आया है।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर मुख्यमंत्री का जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति अपनी असहिष्णुता दोहराई है और सख्त संदेश दिया है। यह फेरबदल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य के लिए मिसाल कायम करेगा। मुख्यमंत्री ने भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है, यदि कहीं भी अनियमितताएं पाई जाती हैं।

मैंडेलसन विवाद में घिरी ब्रिटिश सरकार

ब्रिटेन की राजनीति इन दिनों एक ऐसे विवाद के केंद्र में है, जिसने शासन, सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता के मूल सिद्धांतों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला केवल एक नियुक्ति या बर्खास्तगी का नहीं, बल्कि उस भरोसे का संकट है, जिस पर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव टिकी होती है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, वरिष्ठ नेता पीटर मैंडेलसन और शीर्ष सिविल सेवक ओल्ली रॉबिन्स के इर्द-गिर्द घूमता यह विवाद अब ब्रिटेन की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई, जब पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति सामान्य प्रतीत हो सकती थी, लेकिन बाद में सामने आया कि उनकी सुरक्षा जांच (वेटिंग) को लेकर गंभीर सवाल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें पूरी तरह मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। यहीं से विवाद की जड़ तैयार हुई—क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नियमों को नजरअंदाज किया गया? प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने बाद में कहा कि उन्हें इस महत्वपूर्ण जानकारी की पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताते हुए जिम्मेदारी तय करने की बात कही। लेकिन यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ—अगर प्रधानमंत्री को यह जानकारी नहीं थी, तो आखिर यह चूक किस स्तर पर हुई? इस संदर्भ में सबसे अहम नाम सामने आया ओल्ली रॉबिन्स का, जो उस समय विदेश कार्यालय में शीर्ष पद पर कार्यरत थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने सुरक्षा जांच से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साझा नहीं की। इस आरोप के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। सरकार का तर्क था कि यह गंभीर प्रशासनिक विफलता थी। हालांकि, ओल्ली रॉबिन्स ने इस आरोप को पूरी तरह अलग नजरिए से पेश किया। उन्होंने संसदीय समिति के सामने गवाही देते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर कुछ सूचनाएं साझा नहीं कीं, क्योंकि वे वेटिंग प्रणाली की गोपनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखना चाहते थे। उनका कहना था कि उनका निर्णय पेशेवर था, न कि राजनीतिक। यहीं से यह मामला केवल एक प्रशासनिक निर्णय से आगे बढ़कर राजनीति बनाम सिविल सेवा के टकराव में बदल गया। सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके संगठनों ने इस बर्खास्तगी को लेकर गहरी चिंता जताई। डेव पेनमैन, जो वरिष्ठ सिविल सेवकों के संगठन के प्रमुख हैं, ने कहा कि इस फैसले से पूरी सिविल सेवा में डर का माहौल बन गया है। उनके अनुसार, अब कोई भी अधिकारी यह नहीं समझ पाएगा कि कब राजनीतिक कारणों से उसे पद से हटा दिया जाएगा। पूर्व कैबिनेट सचिव मार्क सेडविल ने भी प्रधानमंत्री से अपील की कि वे अपने आरोप वापस लें और रॉबिन्स को बहाल करें। उनका कहना था कि रॉबिन्स ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक पेशेवर निर्णय लिया था, भले ही वह बाद में गलत साबित हुआ हो। यह बात इस बात का संकेत है कि सिविल सेवा के भीतर इस मुद्दे को लेकर व्यापक असंतोष है। दूसरी ओर, सरकार के भीतर भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन किया, तो कुछ ने इसे गलत ठहराया। पैट मैकफैडन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की, क्योंकि उनके और रॉबिन्स के बीच मूलभूत असहमति थी। वहीं एमिली थॉर्नबेरी ने भी बर्खास्तगी को सही ठहराया, लेकिन उसी समिति के सदस्य डैन कार्डेन ने इसे पूरी तरह गलत बताया। इस विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह ऐसे समय में सामने आया है, जब सरकार को अपनी नीतियों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। लेकिन 'मैंडेलसन प्रकरण' ने पूरी राजनीतिक चर्चा को अपनी ओर मोड़ दिया है। संसद, मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर लगातार इसी मुद्दे पर बहस हो रही है, जिससे सरकार की छवि और कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा है। यह मामला शासन प्रणाली के एक मूलभूत सिद्धांत को भी चुनौती देता है—सिविल सेवा की निष्पक्षता। ब्रिटेन की सिविल सेवा को परंपरागत रूप से राजनीतिक प्रभाव से मुक्त और पेशेवर माना जाता रहा है। लेकिन अगर अधिकारी यह महसूस करने लगें कि उन्हें राजनीतिक कारणों से हटाया जा सकता है, तो यह पूरी व्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है। साथ ही, यह विवाद राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। यदि सुरक्षा जांच जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी, तो यह देश की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संस्थागत महत्व का भी है।

डाउनिंग स्ट्रीट और सिविल सेवा के बीच बढ़ता तनाव इस बात का संकेत है कि भविष्य में निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो सकती है। अधिकारी अधिक सतर्क हो सकते हैं, जिससे निर्णय लेने की गति धीमी पड़ सकती है। कुल मिलाकर, यह पूरा घटनाक्रम ब्रिटेन की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि वे न केवल इस विवाद से बाहर निकलें, बल्कि सिविल सेवा के साथ विश्वास को भी फिर से स्थापित करें। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह विवाद केवल एक अस्थायी राजनीतिक संकट साबित होता है, या फिर यह ब्रिटेन की शासन प्रणाली में एक स्थायी बदलाव की शुरुआत है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 'मैंडेलसन प्रकरण' ने यह दिखा दिया है कि जब राजनीति, प्रशासन और सुरक्षा के बीच संतुलन

बंगाल में 'महा-मतदान'

भारत के लोकतन्त्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब राजनीतिज्ञ अपना रास्ता भटक जाते हैं तो इस देश की जनता आगे बढ़कर उन्हें सही रास्ता दिखा देती है। भारत के चुनावी इतिहास में ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं जब स्वयं जनता ने ही लोगों की निगहबानी की हो। फिलहाल प. बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान व अमेरिका-इजराइल युद्ध की वजह से भारत की ऊर्जा सुरक्षा संकट में पड़ी हुई है और आम लोगों पर भी इसकी आंच आ रही है। इसके बावजूद भारत के इन दोनों राज्यों में राजनीतिक विमर्शों का तीखापन उफान पर है और लोगों पर अपनी मनपसन्द राज्य सरकारों के गठन का जुनून सवार है। इसका प्रमाण यह है कि दोनों ही राज्यों में मतदान जम कर हुआ है। फिर भी प. बंगाल के चुनाव की ज्यादा चर्चा देशभर में इस वजह से है कि इस बार केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से हुकूमत कर रही ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त देना चाहती है। मगर यह काम इतना आसान नहीं है क्योंकि ममता दीदी ने पिछले 30 वर्षों के दौरान राज्य में जिस प्रकार की जन-मूलक राजनीति की उसमें बंगाल के उप-राष्ट्रवाद के उभार के साथ ही बांग्ला संस्कृति की अस्मिता का भाव जनमानस में सिर चढ़कर बोला। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का हिन्दू राष्ट्रवाद का सिद्धान्त बंगाल में दूसरे पायदान पर नजर आता है। इसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं जिसके मूल में बंगाल का भाषाई राष्ट्रवाद प्रमुख है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान बदल कर बांग्लादेश बना उसकी जड़ में समूचे बंगाल का बांग्ला भाषाई राष्ट्रवाद ही था। मगर भारत के प. बंगाल राज्य में आजादी के बाद से ही बांग्ला संस्कृति का प्रादुर्भाव इस प्रकार रहा है कि राज्य की हिन्दू-मुस्लिम जनता 'वन्दे मातरम' को अपना राष्ट्रवादी मन्त्र मानती रही है। इसके साथ ही बंगाल के लोगों के खान-पान में भी हिन्दू-मुस्लिम का बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं रहा है। राजनीति का इन सब चीजों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता है मगर परोक्ष रूप से ये चीजें राजनैतिक विमर्श को एक स्वरूप देने में निर्णायक भूमिका भी निभाती हैं। प. बंगाल के चुनावों का शोर हमें इसलिए भी ज्यादा सुनाई दे रहा है क्योंकि इन चुनावों में राज्य के लगभग 34 लाख मतदाताओं को मत देने के अधिकार से चुनाव आयोग ने वंचित कर दिया है। इस वजह से चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी पूरे देश में विवाद बना हुआ है और यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय तक में कानूनी चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी जानते हैं कि प. बंगाल में 1977 से लेकर 2011 तक वामपंथियों तक एक छत्र राज्य रहा। इस दौरान कम्युनिस्टों ने बंगाल की वह पहचान गायब कर दी जिसके लिए वह अंग्रेजों के शासन के दौर से लेकर विख्यात था। बंगाल की यह प्रसिद्धि इसके औद्योगीकरण को लेकर थी। वामपंथियों ने अपने 34 वर्ष के शासन के दौरान बंगाल को गरीब राज्यों की श्रृंखला में लाकर खड़ा कर दिया। इसका ब्यौरा कई बार राज्यसभा में पूर्व वित्तमन्त्री स्वर्गीय अरुण जेतली ने रखा था।

इन 34 वर्षों में बंगाल से निजी पूंजी निवेश गायब होता चला गया और इस राज्य की बहुसंख्य जनता गरीबी की सीमा रेखा के निकट सरकती चली गई। 2011 में ममता दी ने लगभग 17 साल की कड़ी मेहनत के बाद वामपंथियों के शासन को समाप्त किया। हालांकि राज्य में आजादी के बाद से 1977 तक कमोबेश कांग्रेस पार्टी का राज रहा मगर यह पार्टी वामपंथियों की शासन पद्धति की कम्यून तकनीकों का तोड़ नहीं ढूंढ पाई। इसकी एक वजह यह थी कि वामपंथियों ने कृषि व गांव के मोर्चे पर खेतीहर जमीन का बंटवारा बहुत करीने से किया था। वामपंथी शासन में कृषि के मोर्चे पर बेशक सुधारात्मक काम हुए मगर औद्योगिक मोर्चे पर पहिया उल्टा घूमा। जिसकी वजह से बंगाल के मध्य वर्ग में भारी रोष पैदा हुआ और 2011 में ममता दी ने इस जनरोष को अपने पक्ष में भुनाने में अपार सफलता प्राप्त कर ली।

चूंकि ममता दी 1996 में कांग्रेस से निकल कर ही अपनी अलग तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन किया था अतः इस पार्टी के सभी सक्रिय तत्व उनके साथ जुड़ते चले गये। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रभाव क्षेत्र राज्य में बने रहे जो 2024 के लोकसभा चुनावों में जाकर इसलिए खत्म हुए क्योंकि भाजपा ने चुनावों को सीधे दो कोणीय बना दिया था। इस सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस राज्य की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वामपंथी पार्टियों ने भी 250 से अधिक स्थानों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इससे कई अंचलों में चुनाव के त्रिकोणीय होने की सम्भावना बन गई है जिसका परोक्ष लाभ सत्ताधारी दल को हो सकता है। प. बंगाल में कुल 294 सीटें हैं जिनमें से 152 पर आज मतदान हुआ। मतदान का प्रतिशत 90 के आसपास रहना बताता है कि राज्य के लोगों में राजनीतिक जागरूकता अपने उच्चतम स्तर पर है जिसका अर्थ हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से निकाल रहा है मगर यह उस गुस्से का प्रतीक भी है जो मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ है जिसमें 34 लाख लोग मतदान से वंचित कर दिये गये हैं। जबकि तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के लिए आज ही मतदान हो गया है और वहां भी मतदान का प्रतिशत 80 के करीब है। इस राज्य में फिल्मी कलाकार विजय की पार्टी के लिए युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है जिसका अर्थ निकलता है कि राज्य में द्रमुक व अन्ना द्रमुक की राजनीति के बीच एक तीसरी शक्ति का उदय होने जा रहा है। परन्तु यह दीवानगी राज्य के ग्रामीण मतदाताओं में नहीं है अतः विपक्षी दल अन्ना द्रमुक व विजय की पार्टी के बीच दूसरे स्थान के लिए कांटे की लड़ाई हो सकती है। बंगाल में 29 अप्रैल को शेष सीटों के लिए चुनाव होने हैं और कहा जा सकता है कि उन सीटों पर भी बम्पर मतदान होगा। अतः बम्पर मतदान भारतीय लोकतन्त्र की जीवन्तता को बता रहा है और घोषणा कर रहा है कि जनता राजनीतिक धुंधलके को पूरी तरह छांटने की क्षमता रखती है।

सम्पादकीय...

हंगरी का हिटलर

हंगरी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दर्ज हुआ है, जहां 45 वर्षीय नेता पीटर माग्यार ने लंबे समय से सत्ता में काबिज प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन को चुनाव में पराजित कर दिया। यह परिणाम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ओर्बन पिछले 16 वर्षों से सत्ता में थे। ओर्बन, जिन्हें अक्सर उनकी राष्ट्रवादी नीतियों के कारण आलोचक 'तानाशाह' या 'हंगरी का हिटलर' भी कहते थे। माग्यार, जिन्हें प्रगतिशील यूरोपीय रुख के साथ एक कंजरवेटिव-लिबरल नेता माना जाता है, अगले सप्ताह शपथ लेने वाले हैं। हंगरी की संसद में दो-तिहाई के भारी बहुमत माग्यार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य, न्यायिक स्वतंत्रता और विवादास्पद एनईआर (नेम्जेटी एग्युइमुकोडेस रेंडजेरे) या राष्ट्रीय सहयोग प्रणाली पर ओर्बन युग के कई बदलावों को पलटने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय सहयोग प्रणाली के बारे में विपक्ष का कहना है कि इसने आर्थिक मंदी, घोर भ्रष्टाचार और याराना पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज्म) के साथ-साथ यूरोपीय संघ विरोधी रुख को जन्म दिया है। चुनाव से पहले विक्टर ओर्बन को हाल के संघर्षों में आक्रांता माने जाने वाले तीन शक्तिशाली नेताओं (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू) का समर्थन मिला। ट्रम्प ने तो पिछले हफ्ते बुडापेस्ट में ओर्बन के साथ एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने के लिए उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस को भी भेजा था। ओर्बन ने नेतन्याहू का स्पष्ट रूप से समर्थन किया था। दरअसल, हंगरी ने इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप में वारंट जारी होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय छोड़ दिया था। हंगरी के मतदाताओं का फैसला बिल्कुल स्पष्ट है। उनके फैसले ने हंगरी के ईसाई-राष्ट्रवादी, लोकलुभावन और धुर दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ओर्बन ने रिकॉर्ड कई सालों तक देश की सत्ता संभाली (1998-2002 और 2010-2026)। उन्होंने इस चुनाव से पहले लगातार चार चुनावी जीत हासिल की थीं। ताजा चुनावी नतीजों के मुताबिक, विपक्षी नेता पीटर माग्यार की तिस्जा पार्टी ने लगभग 138 सीटें जीती हैं, जबकि ओर्बन की फिदेस्ज पार्टी को 55 सीटें मिली हैं। पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2010 के दशक में जहां चुनावों के जरिए कई लोकलुभावन नेताओं का उदय हुआ, वहीं हंगरी के चुनाव नतीजों से यह संकेत मिलता है कि दुनिया भर के मतदाता शायद उस धुर दक्षिणपंथी, बहुलवाद-विरोधी, आप्रवासी-विरोधी और विदेशियों के प्रति नफरत से भरी बयानबाजी से थक रहे हैं जिसका उन्होंने समर्थन किया था। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, ब्रिटेन और पोलैंड में हुए चुनावों में भी इसी किस्म के नतीजे देखने को मिले हैं। एक लोकतांत्रिक नेता का असली इम्तिहान सिर्फ चुनाव जीतने में नहीं होता, बल्कि पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने और सरकार बनने के बहुत बाद भी अपने कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली समावेशी नीतियों को आगे बढ़ाने में होता है। विक्टर ओर्बन ने बहुमत के जोर पर मूल संविधान को खत्म कर दिया और खुद को जैसा चाहिए वैसा बदलाव करके नया संविधान विक्टर साहब ने बना लिया। न्याय व्यवस्था को मुट्ठी में कर लिया। मीडिया पर 90 प्रतिशत नियंत्रण हासिल कर लिया और 'क्रोनी कैपिटलिज्म' (पूंजीवादी मित्रवाद) के जोर पर सार्वजनिक संपत्ति अपने ही लोगों की जेब में डाल दी।

भारत नरक नहीं, स्वर्ग का अहसास है, मानवता का वैभव, सभ्यता का प्रकाश है!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अब तक कई बार ऐसे तीखे या अपमानजनक बयान दिए हैं जिनके पश्चात उन्होंने या तो रुख बदल दिया या सॉफ्ट स्टेटमेंट जारी करके अपनी बात पर यू टर्न लेकर साफ साफ मुकर जैसा अंदाज दिखाया है। हाल ही में फिर उन्होंने नरक जैसा देश वाला बयान दिया और फिर यू टर्न ले लिया। उनका रवैया दुनिया का थानेदार समझे जाने वाले सर्वाधिक विकसित और धनी देश अमेरिका के शालीन, सभ्य और सुसंस्कृत होने पर सवालिया निशान लगाने को काफी है। खासकर भारत के खिलाफ जिसका अंतर्राष्ट्रीय आचरण सदैव मर्यादित रहता आया है। भारत पैसे वालों की कद्र नहीं करता, क्योंकि वह तो देशी-विदेशी अपराधियों और वेश्याओं के पास भी खूब होता है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं होती। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका इसी फूहड़ता से ग्रसित है, अभिशप्त है और अंतर्राष्ट्रीय गुंडई में इतना आगे निकल चुका है कि उसके मित्र देश भी उसके साथ खड़े होने में परहेज कर रहे हैं और उसे यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। ईरान-अमेरिका युद्ध ने अमेरिका की पूरी मिट्टी पलीद कर दी है और उसके डीप स्टेट की जो भद्द पिटी है, वैसा कोई उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। शायद इसी खीझ का नाता ट्रंप के नारकीय विवाद से है। आइए, जानते हैं कि सबसे हाल का विवाद 24 घंटे में ही कैसे दोनों पक्षों पर घूम गया, जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट का हिस्सा शेयर किया, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को नरक जैसी जगह बताया गया। इस पोस्ट में भारतीयों के बारे में नस्लवादी टिप्पणी भी थी कि भारत&चीन से लोग अमेरिका आते हैं बस यहीं बच्चे पैदा करने के लिए ताकि उन्हें तुरंत अमेरिकी नागरिकता मिल जाए, जो भारतीय डिप्लोमैसी और जनता के लिए बेहद अपमानजनक माना गया। फिर अगले ही नए बयान में ट्रंप ने रुख पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि समझ में आ गया कि ये मोदी का भारत है, चुपचाप उल्टा लटका देगा। कोई काम नहीं आएगा, जब कूटनीतिक शतरंज की एक चाल चल देगा तो। लिहाजा, उन्होंने जनता के बीच और अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता के जरिए कहा कि भारत एक महान देश है, मजबूत और महान राष्ट्र है और भारत के शीर्ष नेता (प्रधानमंत्री मोदी) के साथ उनकी निजी दोस्ती है। काबिलेगौर है कि इस तरह 24 घंटे के अंदर वही शख्स जो भारत को hard to deal with या नरक जैसी जगह कह चुके थे, उसी देश की तारीफ में बोलने लगे, जिसे राजनीतिक यू टर्न और दबाव में बदला गया माना जा रहा है।

अब इनकी टैरिफ और टैरिफ किंग वाली पुरानी टिप्पणी को स्मरण करा देते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने व्यापार के मसले पर भी दोहरा अपना बयान दिया है। अपने कई इंटरव्यू और भाषणों में उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहा है, और यह कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क लगाने वाले देशों में से एक है, जिससे अमेरिकी उत्पादों को नुकसान होता है। इसी क्रम में उन्होंने भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी, लेकिन एक ही बयान में ही यह भी कहा कि भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, यानी एक ही बयान में औपचारिक तारीफ और व्यावहारिक धमकी दोनों। निष्कर्ष के तौर पर पैटर्न यह दिखता है कि ट्रंप ने भारत के लिए एक बार नफरत भरी, नस्लवादी, नरक जैसा देश वाली भाषा इस्तेमाल की, और फिर तुरंत मिटाने के लिए भारत को महान देश और प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहकर मुकर जैसा कर दिया। वहीं, व्यापार के मोर्चे पर भारत को टैरिफ किंग और हानिकारक बताने के साथ साथ राजनीतिक रूप से अच्छे रिश्ते बताकर दोहरा रुख अपनाया है। इसी प्रकार ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी भी करार दे चुके हैं टैरिफ वार की खीझ में। उनके इस रवैये से भारत का अविश्वास अमेरिका और उनके प्रति बढ़ा है। स्पष्ट है कि अमेरिका के सफल बिजनेसमैन और शातिर राजनेता से राष्ट्रपति बने डॉनल्ड ट्रंप अपने सिरफिरे विचारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब से वो डीप स्टेट के हाथों का खिलौना बने, अपने अनाप-शनाप और अदूरदर्शिता भरे फैसलों से अंतरराष्ट्रीय जगत में अमेरिका की थू-थू करवा रहे हैं। पहले ट्रेड वार और अब सैन्य वार के बाद उनकी जो अंतरराष्ट्रीय फजीहत हुई है, उनके जैसे सो कॉल्ड देश ताकतवर की कलई खुल गई। यूक्रेन से शुरू हुई कूटनीतिक दोगलागिरी ईरान पहुंचते-पहुंचते न केवल चारों खाने चित हो गई, बल्कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी अब समझदार लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। कभी वह भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं, तो कभी नरक जैसा देश! शायद इसलिए कि भारतीय नेतृत्व उनके इशारे पर नहीं थिरक रहा है, जिससे रूस-चीन भी उसे भाव देना बंद कर चुके हैं। दुनिया का थानेदार अमेरिका को वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद जब कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने यह समझ लिया कि रूस-चीन भी उससे डरे हुए हैं। इसी उत्साह में अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर धावा बोल दिया और महज दो माह के भीतर ही परेशान हो उठा। इससे ईरान-रूस-चीन की संयुक्त ताकत का उसको एहसास हुआ। वहीं इसी मुद्दे पर नाटो में फूट भी पड़ गई और यूरोप तटस्थ बन गया। इसी बौखलाहट में ट्रंप भारत और चीन को नरक जैसा बताने लगे। बताते चलें कि भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं को नरक बताने का संदर्भ हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता के मुद्दे पर भारत-चीन को hellhole कहा। यह बयान ट्रंप की इमीग्रेशन पॉलिसी से प्रेरित है, जहां वे आरोप लगाते हैं कि इन देशों से प्रवासी अमेरिका की सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं। जबकि ऐतिहासिक वास्तविकता कुछ और है, जो कई मायने में गौरवशाली भी है। वास्तव में, भारत और चीन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिन्होंने ज्ञान, संस्कृति और व्यापार में दुनिया को प्रभावित किया–चीन भारत को कभी स्वर्ग से बढ़कर मानता था। जबकि अमेरिका की कोई प्राचीन सभ्यता नहीं है, यहां माया-इंका जैसी मूल निवासी सभ्यताएं 3000 ईसा पूर्व की हैं, लेकिन आधुनिक अमेरिका 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय उपनिवेशवाद से उभरा है। अब तो यूरोप भी उससे दूर होते जा रहा है। तो जवाब होगा कि ट्रंप जैसे अपकपाली नेता अमेरिका को स्वर्ग के रूप में पेश करते हैं क्योंकि यह उच्च जीवन स्तर, आर्थिक अवसरों और कानून के शासन के लिए जाना जाता है, लेकिन यह धारणा चुनिंदा है–अमेरिका में भी गरीबी, असमानता और अपराध मौजूद हैं। भारत-चीन की आबादी और विकास चुनौतियां उन्हें नजरअंदाज कर नरक कहना राजनीतिक प्रचार है, जबकि ये देश तेजी से उभर रही महाशक्तियां हैं। ट्रंप को यह समझ लेना चाहिए कि भारत नरक नहीं दुनिया का स्वर्ग है, सर्वोपरि मानवता का वैभव है! अहिंसा का पुजारी है। यहां शाकाहारी मिलते हैं, लेकिन ईसाईयत और इस्लाम की गुलामी के पश्चात यहां मांसाहारी बढ़े और निरीह पशु-पक्षियों की शामत आ गई। पहले धर्म आधारित युद्ध होते थे, लेकिन षड्यंत्र उतना नहीं जितनी कि पिछले 1000-14000 वर्षों में दिखी। कड़वा सच है कि प्राचीन भारत और चीन दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से थे, जिनकी समृद्ध व्यापार, संस्कृति, विज्ञान और वास्तुकला के प्रमाणों से सिद्ध होती है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान के तहत भारत से बौद्ध धर्म चीन पहुंचा, जहां फाह्यान (402 ईस्वी) और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने नालंदा-तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया और ग्रंथ अनुवादित किए। चीन में भारतीय प्रभाव वाले स्थल जैसे युंगांग-लोंगमेन गुफाएं, बिग गूस पगोडा और शाओलिन मंदिर इसकी गवाही देते हैं। वहीं, व्यापारिक समृद्धि के नजरिए से रेशम मार्ग (दक्षिणी समुद्री रूट सहित) से भारत-चीन के बीच रेशम, मसाले, मोती, लोहे के बर्तन और हस्तशिल्प का आदान-प्रदान होता था; रामायण-महाभारत में भी चीन का उल्लेख सोने के भंडार के रूप में है। चोल साम्राज्य ने समुद्री मार्ग सुरक्षित कर व्यापार बढ़ाया। जहां तक वैज्ञानिक योगदान की बात है तो आर्यभट्ट की ज्या तालिका का 8वीं शताब्दी में चीनी अनुवाद हुआ; पाणिनि ने चीनी रेशम को चीनांशुक कहा। खोतान जैसे क्षेत्रों में भारतीय शासन, संस्कृत भाषा और विष्णु पूजा के पुरातात्विक प्रमाण मिले।

प्राचीन भारत और चीन की समृद्धि मिस्र व ग्रीस से व्यापक और निरंतर थी, जहां पूर्वी सभ्यताओं ने आध्यात्मिक-वैज्ञानिक योगदान दिए जबकि पश्चिमी ने स्थापत्य-दार्शनिक। कृषि व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत-चीन की उपजाऊ गंगा-ह्वांगहो घाटियां मिस्र के नील नदी की तरह ही अतिरिक्त उत्पादन देती रहीं, लेकिन सिंधु घाटी की नियोजित शहर व्यवस्था और चीन के रेशम व्यापार ने वैश्विक नेटवर्क बनाया। ग्रीस में मिनोअन-माइसीन व्यापार सीमित था, मिस्र निर्यात-आधारित।

फैमिली आईडी-एक परिवार, एक पहचान, योजना: पारदर्शी और समावेशी शासन की दिशा में एक सशक्त पहल

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सही और पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे, एक बड़ी चुनौती रही है। कई बार योजनाओं की उचित जानकारी, प्रक्रिया की जटिलता और पहचान संबंधी समस्याओं के कारण वास्तविक लाभार्थी इनसे वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फैमिली आईडी एक परिवार, एक पहचान योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है, बल्कि प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करके उन्हें सरकारी सेवाओं से सीधे जोड़ने का कार्य भी करती है। फैमिली आईडी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध क्रियान्वयन और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से प्रत्येक परिवार को एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाती है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बाधा के उन तक पहुंच सके। यह योजना सरकारी सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब किसी परिवार की समस्त जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, तो नागरिकों को बार-बार अलग-अलग विभागों में जाकर दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया तेज, सुगम और अधिक प्रभावी बनती है। फैमिली आईडी योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। इस पहचान संख्या के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी जैसे आय, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक स्थिति आदि एक ही डेटाबेस में संग्रहीत की जाती है। जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड उपलब्ध है, उनके लिए राशन कार्ड संख्या को ही फैमिली आईडी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वहीं जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए अलग से फैमिली आईडी बनाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जहां परिवार स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या लगभग 3.64 करोड़ परिवारों की है, जिनमें करीब 14.60 करोड़ लोग शामिल हैं। इन सभी परिवारों को इस योजना के अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

31 मार्च 2026 तक लगभग 44,32,090 परिवारों की फैमिली आईडी बनाई जा चुकी है, जो इस योजना की सफलता और तेजी से हो रहे विस्तार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश और केंद्र सरकार के 32 विभागों की 98 योजनाओं एवं सेवाओं को फैमिली आईडी डेटाबेस के साथ जोड़ा जा चुका है। राज्य के राशन कार्ड धारक परिवारों (3.64 करोड़ परिवार एवं 14.60 करोड़ व्यक्ति) कि राशन कार्ड संख्या ही उनकी फैमिली आई डी है। ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड नहीं है, कि फैमिली आईडी बनाये जाने के लिए पोर्टल (जिनचरूणि उपसलपकप्ण चण्हलअण्पदद्ध गतिमान है। फैमिली आईडी एक परिवार, एक पहचान योजना के अनेक लाभ हैं, जो इसे एक अत्यंत प्रभावी और नागरिक-केंद्रित पहल बनाते हैं। ये लाभ न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि आम जनता के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में सहायक हैं। इस योजना के तहत सभी डेटा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहता है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आती है। इससे भ्रष्टाचार और फर्जी लाभार्थियों की संभावना कम होती है तथा प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ती है। फैमिली आईडी के माध्यम से प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो रही है कि कौन सा परिवार किस योजना के लिए पात्र है। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक ही पहुंचे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। योजना के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों और उनकी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इससे नागरिकों को अलग-अलग विभागों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और वे एक ही स्थान से अनेक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पहले नागरिकों को हर योजना के लिए अलग-अलग दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते थे, जिससे समय और श्रम दोनों की अधिक खपत होती थी। फैमिली आईडी के माध्यम से यह प्रक्रिया सरल हो गई है और नागरिकों को बार-बार दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह योजना डिजिटल माध्यमों के उपयोग को बढ़ावा देती है, इससे न केवल नागरिकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है। बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फैमिली आईडी के माध्यम से सरकार प्रत्येक परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकती है।

इससे जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें समय पर सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे सामाजिक सुरक्षा तंत्र मजबूत होता है। इस योजना के अंतर्गत एकत्रित डेटा सरकार को सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। इससे सरकार को बेहतर नीतियां बनाने और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक है। फैमिली आईडी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। इससे योजनाओं की पहुंच बढ़ती है और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाते हैं। यह योजना व्यक्ति के बजाय परिवार को एक इकाई के रूप में पहचान प्रदान करती है। इससे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ योजनाओं का लाभ मिल सकता है और उनकी समग्र उन्नति सुनिश्चित होती है। फैमिली आईडी के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है। अधिकारियों को लाभार्थियों की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी हो जाती है। डिजिटल रिकॉर्ड और पारदर्शी प्रणाली के कारण फर्जी लाभार्थियों और बिचौलियों की भूमिका कम हो रही है। इससे योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है।

फैमिली आईडी योजना भविष्य में एक व्यापक पहचान प्रणाली का आधार बन सकती है, जिससे देशभर में एक समान पहचान प्रणाली विकसित की जा सके। फैमिली आईडी योजना डिजिटल इंडिया और सुशासन के सिद्धांतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना तकनीक के माध्यम से शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाती है।

डिजिटल डेटाबेस के माध्यम से नागरिकों की जानकारी सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संग्रहीत की जाती है, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। साथ ही, यह योजना नागरिकों और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। फैमिली आईडी योजना भविष्य में एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास मॉडल का आधार बन सकती है।

यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेंशन, बीमा और अन्य सामाजिक योजनाओं को एकीकृत करने में सहायक हो सकती है। इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि कोई भी पात्र नागरिक सरकारी सहायता से वंचित न रहे। यह योजना समावेशी विकास को बढ़ावा देती है और समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है।फैमिली आईडी एक परिवार, एक पहचान योजना एक दूरदर्शी और प्रभावशाली पहल है, जो प्रशासनिक पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देती है। यह योजना न केवल सरकारी सेवाओं को सरल बनाती है, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ती है। इसके व्यापक लाभों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह योजना उत्तर प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि इस योजना का निरंतर विस्तार और सुधार किया जाता रहा, तो यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है। फैमिली आईडी योजना आधुनिक प्रशासन, तकनीकी प्रगति और नागरिक कल्याण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो एक सशक्त, पारदर्शी और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वरुण ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/38862)

कलेक्ट्रेट सभागार में 'दिशा' समिति की बैठक सम्पन्न, विकास कार्यों की समीक्षा व त्वरित समाधान के निर्देश

कुशीनगर।

कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद विजय कुमार दुबे की अध्यक्षता तथा सह-अध्यक्ष शशांक मणि त्रिपाठी की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक में जल, बिजली, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे प्रमुख मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने कहा कि यह मंच केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता की समस्याओं का त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए। गर्मी को देखते हुए विद्युत व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, जर्जर तारों व पोलों के प्रतिस्थापन तथा मरम्मत कार्य समय से पूरा करने के साथ ही 24 घंटे ड्यूटी सुनिश्चित करने और कर्मियों के संपर्क नंबरों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर

जोर दिया गया। साथ ही हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के सफल आयोजन पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को बधाई देते हुए कहा गया कि इससे कुशीनगर को वैश्विक पहचान मिली है और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं। सह-अध्यक्ष ने अगले 12 महीनों के लिए ठोस विकास रणनीति बनाने पर बल देते हुए कहा कि 15 दिनों के भीतर प्राथमिकताएं तय कर कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने जल, बिजली और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने तथा अधिकारियों को व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने की सलाह दी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में तकनीक के माध्यम से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। दुर्गा फाउंडेशन के साथ एमओयू के तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के छात्रों को कंप्यूटर, एआई व डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ÷जनता दर्शन÷ ऐप के माध्यम से शिकायतों का निस्तारण 5 से 7 दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिजिटल वालंटियर तैयार किए जाएंगे। पुराने डीआईओएस कार्यालय में एआई हब भी स्थापित किया जा रहा है। बैठक में रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्स-रे मशीन, दवाओं की उपलब्धता और 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती जैसे मुद्दे उठाए गए। साथ ही रेलवे अंडरपास व ओवरब्रिज से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विधायक मनीष जायसवाल, सुरेन्द्र सिंह कुशवाहा, मोहन वर्मा, डॉ. असीम कुमार, विवेकानन्द पाण्डेय, विनय प्रकाश गौंड, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल सहित समस्त ब्लॉक प्रमुख एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की पहली बैठक सम्पन्न, विनय प्रकाश गोड़ बने अध्यक्ष

कुशीनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, विधायक फाजिलनगर सुरेन्द्र कुशवाहा, विधायक हाटा मोहन वर्मा, विधायक तमकुही डॉ. असीम कुमार तथा विधायक खड्डा विवेकानन्द पाण्डेय शामिल रहे। बैठक में सर्वसम्मति से विधायक रामकोला विनय प्रकाश गोड़ को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नामित प्रतिनिधि मोहम्मद जफर, डिप्टी कलेक्टर/जिला विकास अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विशुनपुरा, नेबुआ नौरंगिया, मोतीचक व हाटा के ब्लॉक प्रमुख तथा सभी खण्ड विकास अधिकारी

उपस्थित रहे। बैठक में समिति के विस्तार को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तय किया गया कि पांच ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों (जिनमें कम से कम दो महिलाएं हों) को समिति में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन से एक सदस्य तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग से एक-एक प्रतिनिधि को भी नामित किया जाएगा। समिति के प्रमुख कार्यों में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा निधियों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति करना शामिल होगा। आवश्यकता पड़ने पर समिति मामलों को जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी या परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को जांच हेतु प्रेषित कर सकेगी। जिला प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया कि यह समिति जनपद में विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कसया पुलिस ने शराब तस्करी गैंग का किया पर्दाफाश, 65 लाख की अवैध शराब व वाहन बरामद

कुशीनगर। जनपद में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कसया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 204 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को खाद्य सामग्रियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही खेप के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बरामद माल और वाहनों की कुल कीमत लगभग 65 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कसया कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मिनी ट्रक, एक पिकअप, एक डीसीएम और एक मोटरसाइकिल को पकड़कर तलाशी ली, जिसमें खाद्य सामग्री के साथ छिपाकर रखी गई अवैध शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों में अनीश अहमद निवासी रहसु जनोबी पट्टी थाना चौराखास तथा शिशुपाल कुशवाहा निवासी परसौनी फाजिलनगर थाना पटहेरवा शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो शराब को वाहनों में छिपाकर बिहार ले जाता है और वहां ऊंचे दामों पर बेचता है। गिरोह का एक सदस्य मोटरसाइकिल से आगे चलकर पुलिस की गतिविधियों की रेकी करता था। पुलिस ने मु0अ0सं0 0236/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामदगी में 204 पेटी ऑफिसर्स च्वाइस व्हिस्की (कुल 9792 पाउच, 1762.56 लीटर) सहित चार वाहन शामिल हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह, उपनिरीक्षक रूद्रप्रताप सिंह, उपनिरीक्षक जयप्रकाश समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

पंचायती राज दिवस पर सिसवा गोइती में विकास पर मंथन, जनभागीदारी पर जोर

कुशीनगर।

विशुनपुरा विकास खंड अंतर्गत सिसवा गोइती स्थित सीएससी केंद्र पर शुक्रवार को पंचायती राज दिवस के अवसर पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम विकास, स्वच्छता, शिक्षा तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन

जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्राम प्रधान लक्ष्मन गुप्ता ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था गांव के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से पंचायत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील करते हुए गांव को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने का संकल्प दिलाया। बैठक में पंचायत सहायक सकेत मल, दिनेश यादव, हीरा प्रसाद, महंगू प्रसाद, छोटे गुप्ता, कन्हैया प्रसाद, संजय (रोजगार सेवक), उमेश शुक्ला, सुजीत जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग व ग्रामीण उपस्थित रहे।

सफलता पर छात्रों का भव्य स्वागत, विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित

जेईई मेंस में शानदार प्रदर्शन पर स्मृति-चिह्न देकर किया गया सम्मान

भटनी देवरिया।

नगर क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के.के. पब्लिक एकेडमी सीनियर सेकेंडरी, भटनी के मेधावी छात्रों आदर्श दीक्षित एवं आयुष विश्वकर्मा ने जेईई मेंस परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल कर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आदर्श दीक्षित ने 96 पर्सेंटाइल तथा आयुष विश्वकर्मा ने 95 पर्सेंटाइल अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा और मेहनत का शानदार परिचय दिया। छात्रों की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल व्याप्त है। सफलता हासिल करने पर विद्यालय परिसर में दोनों छात्रों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान माल्यार्पण, मिठाई खिलाकर एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया।

विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने छात्रों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रबंधक बी.के. श्रीवास्तव एवं कार्यकारी निदेशक अजय वर्मा ने कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विद्यालय हमेशा से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराता रहा है। इस अवसर पर अभिभावकों ने भी गर्व व्यक्त करते हुए विद्यालय परिवार का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान जे.पी. मिश्रा एवं सभासद दीपक वर्मा का भी सम्मान किया गया।

दिन में मशीन खराब होने की बहाना, रात में लाइट बंद कर दी जा रही तेल

निचलौल।

क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल लेने के लिए लोगों की कतार कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि सभी पंपों पर डीजल और पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है। इसी बीच क्षेत्र के चिउटहा मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप संचालक की मनमानी चरम पर पहुंच चुकी है। क्योंकि पंप संचालक जहां दिन में मशीन खराब होने की बात कहकर लोगों को पंप से बगैर डीजल पेट्रोल दिए ही वापस लौटा दे रहा है। वही संचालक रात में पंप की लाइट बंद कर मोटी रकम लेकर डीजल पेट्रोल का वितरण कर रहा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पंप संचालक के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है। लोगो ने अधिकारियों से जांच कर पंप संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो को अमर उजाला पुख्ता नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में

दिन में तेल लेने के लिए पम्प पर उमड़ी लोगो की भीड़

देखा जा रहा है कि पंप की लाइट बंद कर दी गई है।

अंधेरे में कुछ लोग बाइक के साथ डब्बे लेकर पहुंचे है। वही पंप संचालक की ओर से बंद लाइट के बीच उन लोगों को डीजल और पेट्रोल दिया जा रहा है। शुक्रवार को पंप पर तेल लेने के लिए पहुंचे हीरा, भुनेश्वर, कलामुद्दीन, हिरदेश, चंदन आदि ने बताया कि पंप पर पिछले कई दिनों से डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है। लेकिन जरूरतमंदों को डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा हैं। वही ब्लैक करने वाले लोगों को पंप संचालक की ओर से रात के अंधेरे में मोटी रकम वसूल कर तेल दिया जा रहा है। जबकि दिन में तेल के लिए पम्प पर पहुंचते ही कभी मशीन खराब तो कभी टेक्निकल दिक्कत होकर तेल न देने की बहाना कर वापस लौटा दिया जा रहा है। ऐसे में अगर पंप संचालक के खिलाफ जल्द जांच कर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वह लोग सड़क पर उतर आंदोलन करेंगे।

पेट्रोल पंप संचालक की बढ़ती मनमानी को लेकर क्षेत्र के लोगों में बढ़ रहा आक्रोश

इस मामले में पूर्ति निरीक्षक इंद्रभान सिंह ने बताया कि उक्त पम्प संचालक की काफी शिकायत मिल रही है। पिछले दिनों भी शिकायत मिलने पर पंप पर पहुंच तेज को वितरण कराया गया था। मामले की जल्द जांच कर विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजी जाएगी।

आईआरएस अफसर की बेटी की हत्या- नाक की हड्डी टूटी, शरीर के दूसरे हिस्सों में मिले फ्रैक्चर, पोस्टमार्टम में खुलासा

नई दिल्ली। सट्टेबाजी के कर्ज में डूबे राहुल मीणा ने नौकरी से निकाले जाने की खुन्नस में आईआरएस अधिकारी की बेटी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। डेढ़ माह पहले काम से निकाले गए आरोपी ने घर में घुसकर युवती पर बर्बरता से हमला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाक की हड्डी समेत शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर मिले हैं। आरोपी ने युवती को धमकाते हुए लॉकर खोलने को कहा था, मना करने पर उसने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को एक ओयो होटल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को ही एम्स मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर युवती का शव परिवार के हवाले कर दिया था। पीएम रिपोर्ट में युवती के साथ हुई बर्बरता के कई निशान मिले हैं। उसकी नाक की हड्डी के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों में फ्रैक्चर मिले हैं। इसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि कर्ज में डूबा राहुल आईआरएस अधिकारी के घर में नौकरी के दौरान सामान लाने में रुपयों की हेराफेरी करने लगा। युवती ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राहुल की हेराफेरी की आदत बढ़ गई तो डेढ़ माह पहले उसने पिता से उसकी शिकायत कर दी। आईआरएस अधिकारी ने राहुल को पहले डांटा फिर उसे काम से निकाल दिया। पुलिस का मानना है कि इसी नाराजगी में आरोपी ने लूट की वारदात को अंजाम देने के दौरान हैवानियत की सारी हद को पार करते हुए युवती से दुष्कर्म किया और उसकी जान ले ली। आईआरएस अधिकारी ने आरोपी को डेढ़ माह पहले काम से निकाल दिया तो आरोपी राजस्थान अलवर वापस लौट गया। हालांकि पुलिस पूछताछ में आरोपी पुलिस के सामने लूटपाट की बात ही बता रहा है। उसने दुष्कर्म और हत्या क्यों की इस पर आरोपी गोल-मोल जवाब दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि नौकरी जाने के बाद वह युवती और उसके परिवार के प्रति गुस्सा रखता था। जांच एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम को आरोपी की व्यक्तिगत रंजिश, आर्थिक स्थिति और आपराधिक प्रवृत्ति से जोड़कर देख रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। करीब एक साल पहले आरोपी राहुल के मामा की सिफारिश पर आईआरएस अधिकारी ने राहुल मीणा को काम पर रखा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। बृहस्पतिवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब पुलिस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने के लिए आरोपी को लेकर अलवर राजस्थान के अलावा उन सब जगह लेकर जाएगी, जहां-जहां आरोपी रुका था। आईआरएस अधिकारी और उनकी पत्नी बुधवार सुबह करीब 8 बजे जिम से अपने घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बेटी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। दंपती ने बिना देर किए बेटी को उठाया और अपनी कार में डालकर उसे ओखला स्थित फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल ले गए। सुबह करीब 8.49 बजे अस्पताल से ही पुलिस को खबर दी गई। पुलिस की एक टीम अस्पताल व दूसरी टीम कैलाश हिल स्थित उनके घर पहुंची। पुलिस जहां पहुंची तो घर का नजारा देखकर उनके भी रोंगटे खड़े गए। घर में चारों ओर खून बिखरा पड़ा था। घर में दूर तक खून के छींटे फैले थे। इस बीच पुलिस उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त और विशेष आयुक्त भी मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम व एफएसएल की टीम भी वहां पहुंच गई।

बीजेपी में होकर भी पार्टी के नहीं हो पाए राघव चड्ढा समेत आप के बागी सांसद

नई दिल्ली।

राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. राघव चड्ढा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इसका ऐलान किया. उन्होंने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी की. हालांकि राघव ने जिन 7 सांसदों के बीजेपी में विलय होने की बात कही उनमें से चार आज मौजूद नहीं थे. राघव ने कहा कि पार्टी के दो तिहाई सांसद इस पहल में उनके साथ हैं. लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर राघव और अन्य सांसद बीजेपी का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. उनके बीजेपी में शामिल होने के पीछे एक तकनीकी अड़चन है. आइए पूरी बात समझते हैं.

क्या है तकनीकी अड़चन?

राघव चड्ढा ने दो अन्य सांसदों के साथ आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. नितिन नवीन ने उन्हें मिठाई खिलाकर स्वागत भी किया, लेकिन अभी तक पार्टी ने उनकी आधिकारिक ज्वाइनिंग नहीं हुई है. इसके पीछे एक तकनीकी अड़चन है. ये नेता बीजेपी में आधिकारिक तौर पर तभी शामिल हो सकते हैं, जब उन्हें राज्यसभा के सभापति से मंजूरी मिल जाए.

राघव चड्ढा ने राज्यसभा सभापति को सौंपा पत्र

नितिन नवीन से मुलाकात के बाद, बागी सांसदों ने मीडिया से कोई बात नहीं की. हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने ऐलान किया था कि वो आम आदमी पार्टी के दो तिहाई सांसदों के साथ बीजेपी में विलय कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने राज्यसभा के सभापति को सभी बागी सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र भी सौंप दिया है.

उन्होंने कहा कि ये पत्र सभापति को खुद उन्होंने ही जाकर सौंपा. राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज, भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (आप) के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने भाजपा में विलय कर लिया है. सात सांसदों ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के अध्यक्ष को सौंपा गया था. मैंने, दो अन्य सांसदों के साथ, व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज सौंपे.

आप के बाकी 4 बागी सांसद कहां?

आम आदमी पार्टी के जिन सात राज्यसभा सांसदों ने अपने गुट को बीजेपी में विलय किया उनमें से केवल तीन ही मीडिया के सामने आए और फिर बाद में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. सवाल है कि बाकी चार सांसद कहां हैं और अपने साथियों के साथ नजर क्यों नहीं आए? सूत्रों के मुताबिक-

स्वाति मालीवाल- पूर्वोत्तर में छुट्टी पर है

हरभजन सिंह- आईपीएल में व्यस्त है

राजेंद्र गुप्ता- इलाज के लिए विदेश में है।

विक्रमजीत साहनी- दिल्ली में है लेकिन तबीयत का हवाला देकर बात नहीं कर रहे

राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा,'आप, जिसे मैंने अपने खून-पसीने से सींचा और जिसे मैंने अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिक मूल्यों से पूरी तरह भटक गई है. पार्टी अब देश के लिए नहीं, बल्कि अपने ही फायदे के लिए काम कर रही है. पिछले कुछ वर्षों में, मुझे यह महसूस होने लगा है कि मैं गलत पार्टी में सही व्यक्ति हूं. आज, मैं आप से अलग होने और जनता के साथ अधिक निकटता से काम करने के अपने निर्णय की घोषणा करता हूं।

ये बंदेखानी पार्टी है, बंदे खाकर डकार नहीं मारते- भगवंत मान

चंडीगढ़। (वेबवार्ता) आप के सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में जाने पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नीदरलैंड दौरे से लौटे सीएम भगवंत मान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मान ने कहा कि ये पंजाब की इमेज खराब करने की कोशिश है। भाजपा ने पंजाबियों के साथ गद्दारी की। पंजाब में अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की पास अपना कुछ नहीं है, पंजाब में कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंदेखानी पार्टी है, ये बंदे खाकर डकार नहीं मारते। मान ने कहा कि अब राघव चड्ढा का दम घुटने लगा है। पार्टी ने उन्हें इतना कुछ दिया तो उसका वो मान रखो। भाजपा कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी को तंग कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ ईडी और सीबीआई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब के लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तो रवनीत बिट्टू राघव चड्ढा को भला बुरा कह रहा था, अब एक साथ कैसे बैठेंगे। ये पंजाब के गद्दार हैं। इन्हें पंजाब के लोग सजा देंगे। इनके जाने से भाजपा मजबूत नहीं होगी। उसमें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए थे। वे ही अब कह रहे हैं कि उनकी कोई बात नहीं सुनता। मान ने कहा कि पार्टी बड़ी होती है, उसके नेता नहीं। ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी जो भगवंत मान को खरीद सके। थोड़ा दुख हुआ है, लेकिन समंदर में से एक लोटा पानी कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पंजाब के नहीं हुए, वे भाजपा के क्या होंगे। पार्टी ने सभी को मान दिया, लेकिन किसी के दिल में क्या है, हम नहीं जान सकते।

ममता बनर्जी का भाजपा पर तीखा हमला

वे झालमुड़ी का वादा कर रहे हैं, मैं भेलपुरी खिलाऊंगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बौबाजार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे झालमुड़ी का वादा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको भेलपुरी खिलाऊंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि झारग्राम में प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने का कार्यक्रम पहले से तैयार किया गया था। ममता बनर्जी ने दावा किया कि दुकान पर पहले से सीसीटीवी और टीवी कैमरे लगाए गए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सुरक्षा के नाम पर झालमुड़ी घर से बनाकर लाई गई थी और दुकानदार को सिर्फ 10 रुपये दिए गए। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि जीतने पर झालमुड़ी खाएंगे, लेकिन मैं कहती हूं कि दिल्ली से आपको भेलपुरी खिलाऊंगी। चुनाव जीतने के लिए झालमुड़ी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, हम तीनों झालमुड़ी के आदी हैं, लेकिन क्या आपने कभी मछली और चिकन करी खाई है? मैं आपका ढोकला खाती हूं, डोसा खाती हूं, लिट्टी, ठेकुआ और सत्तू भी खाती हूं। ईद पर सेवइयां और हलवा भी खाती हूं, मुझे धर्म मत सिखाइए।

सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

कांग्रेस समेत विपक्ष के 73 सांसदों ने दिया नोटिस

नई दिल्ली।

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 73 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रपति को एक नोटिस सौंपा है।

कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सांसदों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की मांग की है।

महाभियोग की मांग के प्रमुख बिंदु

सांसदों द्वारा सौंपे गए नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त पर सिद्ध कदाचार का आरोप लगाया गया है। यह कदाचार 15 मार्च 2026 को या उसके बाद किए गए कार्यों और चूक से संबंधित है। इस आरोप को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के साथ-साथ अनुच्छेद 124 (4) के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11 (2) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत वर्णित किया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नौ विशिष्ट आरोप

जयराम रमेश के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नौ विशिष्ट आरोप हैं, जिन्हें विस्तृत रूप से प्रलेखित किया गया है और जिन्हें नकारा या छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद पर बने रहना संविधान पर हमला है और यह अत्यंत शर्मनाक है कि वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर काम कर रहे हैं।

संवैधानिक प्रावधान और प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है।

इसके लिए संसद के दोनों सदनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा, द्वारा एक ही सत्र में उस प्रस्ताव का समर्थन करना आवश्यक है, जिसमें कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत का समर्थन हो। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968, इस प्रक्रिया के लिए विस्तृत नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं। इन प्रक्रियाओं में आरोपों की जांच, गवाहों के बयान और बचाव का अवसर शामिल होता है।

क्या है विपक्षी दलों की चिंताएं?

विपक्षी दलों ने लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, खासकर हाल के वर्षों में। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम कर रहा है और महत्वपूर्ण निर्णयों में पारदर्शिता का अभाव है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की मांग इसी चिंता का एक बड़ा प्रकटीकरण है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विपक्षी दलों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भंडारा में शादी से लौट रही कार की ट्रक से भिड़ंत, पांच लोगों की मौत

नई दिल्ली। शादी समारोह से घर लौटते समय मारुति ओमनी और ट्रक की जोरदार टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा गुरुवार रात महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हुआ। मृतकों में दूल्हे के चाचा-चाची भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, हादसा पावनी तहसील के अड्याल गांव के पास हुआ। शादी पार्टी के लोग मारुति ओमनी में सवार थे। तेज रफ्तार से जा रही कार का अचानक टायर फट गया, जिससे ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और कार सामने चल रहे ट्रेलर ट्रक से टकरा गई।

रामधारी सिंह दिनकर की 52वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने किया नमन, कहा- आज से रश्मिरथी हीरक जयंती वर्ष पर्व की शुरुआत

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रामधारी सिंह दिनकर की 52वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि आज से दिनकर की अमर कृति रश्मिरथी के हीरक जयंती वर्ष पर तीन दिवसीय पर्व की शुरुआत होगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज लखनऊ में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति रश्मिरथी के हीरक जयंती वर्ष और उनकी 52वीं पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में तीन दिवसीय रश्मिरथी पर्व का आरंभ होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक चेतना, समता और समरसता के विचारों को फिर से स्मरण करने का सुअवसर है। इस अवसर पर स्मारिका रश्मिरथी से संवाद का विमोचन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रकवि दिनकर जी के ओजस्वी विचारों को नमन करते हुए इस आयोजन में सहभागी बनूंगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर, 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। रश्मिरथी (1952) दिनकर की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है।

तेजस्वी यादव का बड़ा दावा- बीजेपी ने नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए विवश किया, क्योंकि वह उन्हें राजनीतिक रूप से समाप्त करना चाहती थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाजपा नेता सम्राट चौधरी नीत सरकार द्वारा पेश विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। यादव ने कहा, हमें पहले से पता था कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। भाजपा लगातार कहती रही कि 2030 तक नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेता रहेंगे, लेकिन अब उसने उन्हें समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा, किसी भी राज्य को राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है, लेकिन बिहार की स्थिति अलग है। यहां पांच वर्षों में पांच सरकारें देखी गई हैं। तेजस्वी का संकेत उस अवधि की ओर था, जिसमें जद(यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार राजग में आते-जाते रहे। भाजपा के भीतर असंतोष का संकेत देने का प्रयास करते हुए तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के शुरुआती राजनीतिक जीवन का उल्लेख किया, जब वह राजद में थे। उन्होंने कहा, मुझे सम्राट चौधरी के लिए प्रसन्नता है, जो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पाठशाला से निकले हैं। लेकिन उन्हें भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में गहरी जड़ें रखने वाले उन लोगों से सावधान रहना चाहिए, जो उनके उभार से नाराज हैं। राजद नेता ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनि चौधरी के एक पुराने चुनावी भाषण का भी उल्लेख किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, शकुनि चौधरी ने नरेन्द्र मोदी को जीवित दफनाने की धमकी दी थी। प्रतीत होता है कि इससे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भयभीत हो गया और उन्हें शांत करने के लिए उनके पुत्र को मुख्यमंत्री बना दिया। तेजस्वी यादव ने महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर जारी बहस का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए, जिससे वंचित जातियों की महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

आतंकवादी टिप्पणी पर ईसीआई ने मांगा जवाब, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे बोले- हमने रिप्लाई कर दिया है

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी आतंकवादी टिप्पणी के संबंध में चुनाव आयोग के नोटिस पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा कि हमने पहले ही जवाब दे दिया है; यह अखबार में छप चुका है। यह घटना कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को लिखे पत्र के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की इस बात के लिए आलोचना की थी कि खरगे को आरोपों का जवाब देने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया गया है। पार्टी ने विस्तृत जवाब तैयार करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। ईसीआई को लिखे पत्र में जयराम रमेश ने लिखा कि हम कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस में लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए दिए गए कम समय, यानी 24 घंटे, पर आश्चर्य व्यक्त करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि यह समय बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष कई चुनाव प्रचारों में व्यस्त हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हम एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय चाहते हैं और साथ ही कांग्रेस नेताओं के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल को इसे प्रस्तुत करने का भी समय चाहते हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार को खरगे को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गई उनकी विवादास्पद टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगा। खरगे ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाए जाने का जिक्र किया।

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा कि हमने पहले ही जवाब दे दिया है; यह अखबार में छप चुका है।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री राजनेताओं को डरा रहे हैं और कर आतंकवाद हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को एएनआई से कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री राजनेताओं और उम्मीदवारों को डरा रहे हैं और इस संबंध में मैंने कहा कि कर आतंकवाद हो रहा है, ईडी छापेमारी कर रही है, आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है, सीबीआई छापेमारी कर रही है। इस आतंकवाद को प्रधानमंत्री बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा। वे लोगों को डरा रहे हैं। वे छापेमारी के जरिए लोगों को चुप कराने और चुनाव में उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं। चेन्नई में मैंने यही कहा था।